

नवभारत

5

पीएम मोदी से मिले चंद्रबाबू नायडू

6

उद्यमी आत्मनिर्भर भारत का निर्माण कर रहे हैं

7

7.76 लाख चालक और 40.84 लाख ग्राहक जुड़े

8

पीवी सिंधु और आयुष ने जीत से किया चाइना ओपन आगाज

सड़क से संसद तक हंगामा

दिल्ली, भोपाल, जयपुर, पटना, हैदराबाद समेत कई शहरों में प्रदर्शन

नई दिल्ली, 22 जुलाई. संसद के मानसून सत्र के दौरान बुधवार तीसरे दिन भी विपक्ष ने काँकरोच जनता पार्टी के समर्थकों पर पुलिस कार्रवाई के मुद्दे पर हंगामा किया। वहीं कांग्रेस के कई नेता काला कपड़े पहनकर संसद में आएँ. संसद के दोनों सदनों में विपक्ष के हंगामे से कार्यवाही प्रभावित रही.

राज्यसभा में मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि, वे सदन में नीट पेपर लीक मामले में चर्चा तभी चाहते हैं जब शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दे दें. जबकि दिल्ली में सुरक्षा के कड़े इंतजामों के बीच कई मेट्रो स्टेशन बंद किए गए. प्रश्न काल और शून्य काल नहीं हो सका और सदन की कार्यवाही दिगभर के लिए स्थगित कर दी गयी. समाजवादी पार्टी (सपा) के अखिलेश यादव ने कहा कि पेपरलीक मुद्दा कांग्रेस, भारतीय जनता पार्टी और सपा का नहीं है, यह सभी लोगों से जुड़ा मसला है. इसके लिए सभी राजनीतिक दल लड़ रहे हैं. उन्होंने कहा, विद्यार्थियों के साथ पुलिस ने बर्बरता की, बेटियों के कपड़े फाड़े गये.



वहीं, देशभर में छात्रों का आक्रोश बुधवार को सड़कों पर दिखाई दिया. पटना, हैदराबाद, पुणे, भोपाल और बेंगलुरु समेत कई शहरों में हजारों छात्रों और छात्र संगठनों ने शिक्षा व्यवस्था, कथित पेपर लीक और दिल्ली में छात्रों पर हुई पुलिस कार्रवाई के विरोध में प्रदर्शन किए। प्रदर्शनकारियों ने केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे, परीक्षा प्रणाली में पारदर्शिता और पूरे मामले की न्यायिक जांच की मांग उठाई।

दिल्ली मेट्रो के 16 स्टेशनों को बुधवार को सुरक्षा कारणों से अगले आदेश तक बंद कर दिया गया. वहीं देर शाम सभी स्टेशनों को बहाल कर दिया गया. हालाँकि, राजीव चौक, मंडी हाउस और सेंट्रल सेक्रेटेरिएट स्टेशनों पर इंटरचेंज की सुविधा दिन से जारी थी. इससे पहले रविवार को भी सुरक्षा कारणों से जनपथ, राजीव चौक, पटेल चौक, सेंट्रल सेक्रेटेरिएट और सेवा तीर्थ मेट्रो स्टेशनों को अगले आदेश तक बंद किया गया था.

सुप्रीम कोर्ट ने काँकरोच जनता पार्टी समर्थकों पर हुए लाठीचार्ज के खिलाफ दायर याचिका पर तुरंत सुनवाई से इनकार कर दिया है. बुधवार को एक वकील ने सीजेआई की अगुआई वाली 3 जजों की बेंच के सामने जनहित याचिका लगाई थी. सीजेआई सुर्यकांत ने कहा, हमें वीडियो देखने में कोई रुचि नहीं है.

केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री किरेंन रिजिजू ने स्पष्ट कहा कि केंद्र सरकार नीट पेपर लीक और उससे जुड़े सभी मुद्दों पर संसद में विस्तृत चर्चा के लिए पूरी तरह तैयार है. उन्होंने विपक्ष से अपील की कि वे ऐसी शर्तें न लगाएं जिससे चर्चा ही शुरू न हो सके.

पुलिस और केंद्र को हाईकोर्ट का नोटिस दिल्ली हाईकोर्ट में स्टूडेंट्स से मारपीट के मामले में अर्जों पर सुनवाई हुई. हाईकोर्ट ने सरकार से कहा- मारपीट के सीसीटीवी फुटेज सुरक्षित रखे जाएँ. दिल्ली हाईकोर्ट दिल्ली पुलिस और केंद्र सरकार को नोटिस भेजा. हाईकोर्ट ने ये भी कहा कि चार हफ्तों में इसका जवाब दें.

10 साल में 152 पेपर हुए लीक

दिल्ली में छात्रों के खिलाफ लाठीचार्ज पर राहुल ने की प्रेस कॉन्फ्रेंस

नई दिल्ली, 22 जुलाई. राहुल गांधी ने बुधवार को दिल्ली के इंदिरा भवन में छात्रों के खिलाफ लाठीचार्ज पर प्रेस कॉन्फ्रेंस की. उन्होंने कहा कि प्रश्न-पत्रों के लीक होने के मामलों से लगभग 7.5 करोड़ परिवार प्रभावित हुए हैं. राहुल ने कहा कि केंद्र का शिक्षा बजट 1.4 लाख करोड़ रुपये का है, जबकि विद्यार्थी नीट परीक्षा के लिए अपने परिवार के पैसे से 1.32 लाख करोड़ रुपये खर्च करते हैं.



उन्होंने आरोप लगाया कि मोदी सरकार प्रतियोगी परीक्षाओं की शुद्धता बनाये रखने में नाकाम रही है और लाखों युवाओं का भविष्य अंधेरे में डाल दिया है.

उन्होंने कहा कि 10 साल में 152 पेपर लीक हुए हैं. वहीं, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने देर शाम प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सरकार का रुख साफ किया है. नड्डा ने छात्रों की चिंताओं को बिल्कुल जायज माना है. उन्होंने इस गंभीर मुद्दे पर कोई राजनीति नहीं होनी चाहिए. विपक्ष को इससे राजनीतिक फायदा उठाने की कोशिश नहीं करनी चाहिए. नड्डा ने कहा कि जहां विपक्ष की सरकारें थीं और वहां भी पेपर लीक जैसी घटनाएं सामने आई थीं

सीजेपी ने टुकराई बातचीत की पेशकश

नई दिल्ली, 22 जुलाई. काँकरोच जनता पार्टी ने बुधवार को सरकार की तरफ से बातचीत की पेशकश टुकरा दी. सीजेपी प्रवक्ता सीरव दास ने कहा कि वे बातचीत के लिए किसी के घर या दफ्तर नहीं जाएंगे. गुरुग्राम के मेदांता अस्पताल में भर्ती वांगचुक ने केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा और जितेंद्र सिंह को चिट्ठी लिखी. उन्होंने कहा कि बच्चों के खिलाफ कोई एक्शन न हो. सरकार भरोसा दे तो वे अनशन खत्म कर सकते हैं. वहीं देर रात जेपी नड्डा और जितेंद्र सिंह वांगचुक से मिलने अस्पताल पहुंचे थे.

एमपी के सीएस अनुराग जैन बने नीति आयोग के नए सीईओ

नई दिल्ली/भोपाल, 22 जुलाई. केंद्र सरकार ने मध्यप्रदेश के मुख्य सचिव अनुराग जैन को नई जिम्मेदारी सौंपते हुए उन्हें नीति आयोग का मुख्य कार्यकारी अधिकारी नियुक्त किया है. मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति की मंजूरी के बाद कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग ने इस संबंध में आदेश जारी कर दिए हैं.

आदेश के अनुसार अनुराग जैन पदभार ग्रहण करने की तारीख से नई जिम्मेदारी संभालेंगे और अपने स्वीकृत सेवा विस्तार की



अवधि पूरी होने के बाद भी दो वर्ष अथवा अगले आदेश तक, जो भी पहले हो, इस पद पर कार्य करेंगे. 1989 बैच के मध्यप्रदेश कैडर के वरिष्ठ आईएएस अधिकारी अनुराग जैन वर्तमान में राज्य के मुख्य सचिव हैं.

एक नजर में

आतंकी हमले में एक पुलिसकर्मी शहीद

श्रीनगर. दक्षिण कश्मीर के अर्न्तनाग जिले के लाल चौक क्षेत्र में बुधवार को आतंकियों ने पुलिस पर हमला कर दिया. कोकरनाग रोड पर नियमित गश्त के दौरान ड्यूटी पर तैनात हेड कांस्टेबल आशिक हुसैन कुरैशी को आतंकियों ने निशाना बनाकर गोली मार दी. गोली लगने से वह गंभीर रूप से घायल हो गए. घटना के तुरंत बाद स्थानीय लोगों की मदद से उन्हें सरकारी मेडिकल कॉलेज अर्न्तनाग अस्पताल पहुंचाया गया, जहां उपचार के दौरान डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया. प्रारंभिक जानकारी के अनुसार, हमलावर एक वाहन में सवार होकर आए और अवाक हेड कांस्टेबल पर अंधाधुंध फायरिंग कर मौके से फरार हो गए. हमले के बाद पूरे क्षेत्र में अफरा-तफरी का माहौल बन गया.

106 अरब यूनिट बिजली में भारत की नई उड़ान

नई दिल्ली. भारत में नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र लगातार नई ऊचाइयों को छू रहा है और पवन ऊर्जा इसका प्रमुख आधार बनकर उभरी है। लोकसभा में नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के राज्य मंत्री श्रीपद येसो नाइक ने लिखित जवाब में बताया कि देश में विंड एनर्जी परियोजनाओं की कुल स्थापित क्षमता बढ़कर 57,443 मेगावाट हो गई है। वहीं, वित्त वर्ष 2025-26 के दौरान इन परियोजनाओं से 106 अरब यूनिट बिजली का उत्पादन दर्ज किया गया.

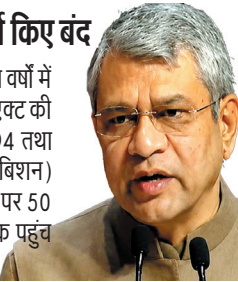
गुस्ताखी माफ



अश्लील कंटेंट पर सरकार की बड़ी कार्रवाई

नई दिल्ली, 22 जुलाई. केंद्र सरकार ने पिछले दो वर्षों में अश्लील कंटेंट दिखाने और इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट सहित अन्य कानूनी प्रावधानों का उल्लंघन करने के आरोप में 50 ओटीटी प्लेटफॉर्म की भारत में सार्वजनिक पहुंच बंद कर दी है.

यह जनकारी केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बुधवार को लोकसभा में दी. लोकसभा में केंद्रीय मंत्री ने बताया कि यह कार्रवाई उन इंटरमीडियरी और ओटीटी प्लेटफॉर्म के खिलाफ की गई,



जिन्होंने इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट, 2000 की धारा 67 और 67ए, भारतीय न्याय संहिता की धारा 294 तथा इंडीसेंट रिप्रिजेंटेशन ऑफ वुमेन एक्ट, 1986 की धारा 4 का उल्लंघन किया. उन्होंने बताया कि सरकार

शिकायत मिलने पर कार्रवाई करती है और आईटी एक्ट की धारा 79(3)(बी) के तहत मिली शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए इंटरमीडियरी को गैरकानूनी कंटेंट हटाने या उस तक पहुंच रोकने के निर्देश देती है.

पुराने वाहनों में माइलेज थोड़ा घट सकता है, इंजन को नुकसान नहीं



नई दिल्ली, 22 जुलाई. ई20 पेट्रोल को लेकर चले तमाम तरह के अफवाहों पर विराम लगाते हुए केंद्र सरकार ने स्थिति साफ किया है. केंद्र सरकार ने बुधवार को

कहा कि ई20 पेट्रोल के इस्तेमाल से ई10 पेट्रोल के लिए डिजाइन किए गए कुछ पुराने वाहनों में ईंधन दक्षता में मामूली कमी आ सकती है. हालाँकि, एथेनॉल मिश्रित पेट्रोल के कारण बड़े पैमाने पर इंजन खराब होने या वाहनों में खराबी आने का कोई सत्यापित प्रमाण नहीं मिला है. प्राकृतिक गैस राज्य मंत्री सुरेश गोपी ने बताया कि ई10 के लिए डिजाइन किए गए पुराने वाहनों में माइलेज में होने वाली कमी आमतौर पर करीब 3 से 5 प्रतिशत तक ही सीमित रहती है.

सरकार का नजदीक जगह देने का भरोसा

भोजशाला विवाद

► नमाज स्थल पर सुप्रीम कोर्ट में फिर सुनवाई

► मुस्लिम पक्ष ने वैकल्पिक जमीन पर उठाए सवाल



गई जमीन भोजशाला से काफी दूर है, जबकि अदालत के निर्देश के अनुसार नमाज के लिए स्थान नजदीक होना चाहिए था. सुनवाई के दौरान राज्य सरकार ने मामले को देखने और जरूरत पड़ने पर नजदीक स्थान उपलब्ध कराने की बात कही. मुस्लिम पक्ष की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता हुजैफा अहमदी ने अंतरिम आवेदन पर जल्द सुनवाई का आग्रह करते हुए

कहा कि वैकल्पिक स्थल की दूरी के कारण एक शुक्रवार की नमाज पहले ही नहीं हो सकी है. उन्होंने अदालत के आदेश के अनुरूप व्यवस्था किए जाने की मांग रखी. राज्य सरकार की ओर से पेश सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि वह स्वयं मामले को देखेंगे और आवश्यक सुधार के लिए कदम उठाए जाएंगे. उन्होंने बताया कि प्रशासन से समन्वय कर वैकल्पिक व्यवस्था पर विचार किया जाएगा. सुनवाई के दौरान न्यायमूर्ति जॉयमाल्या बागची ने कहा कि अदालत के आदेश का पालन उसकी भावना के अनुरूप भी होना चाहिए.

बैठक में बड़े फैसले 2 सितंबर को होगी अगली बैठक

पांच संत संभालेंगे राम मंदिर ट्रस्ट की कमान

अयोध्या, 22 जुलाई. श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की बुधवार को आयोजित बैठक में मंदिर के प्रशासनिक, धार्मिक और संगठनात्मक ढांचे से जुड़े कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए.

अब राम मंदिर ट्रस्ट की कमान पांच संत संभालेंगे. ट्रस्ट का पहला मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सीईओ) अभी नियुक्त नहीं किया जाएगा और इस पद पर चयन एक महीने बाद

ट्रस्ट ने सीईओ पद के लिए 18 जुलाई तक आवेदन आमंत्रित किए थे. प्राप्त आवेदनों की जांच और मूल्यांकन विशेषज्ञ समिति द्वारा किया जा रहा है. इस समिति में सेवानिवृत्त न्यायमूर्ति प्रमोद कोहली, सेवानिवृत्त लेफ्टिनेंट जनरल विष्णुकांत चतुर्वेदी तथा एनआईटी रायपुर के पूर्व अध्यक्ष सुरेश हवारे शामिल हैं. समिति की सिफारिशों के आधार पर अंतिम निर्णय ट्रस्ट करेगा. बैठक में ट्रस्ट के रिक्त पदों, प्रशासनिक सुधारों और मंदिर के दैनिक संचालन को अधिक प्रभावी बनाने पर भी विचार-विमर्श हुआ. ट्रस्ट के अनुसार अगली बैठक 2 सितंबर को आयोजित की जाएगी, जिसमें नए महासचिव और पहले सीईओ के नामों की घोषणा किए जाने की संभावना है.

किया जाएगा. साथ ही ट्रस्ट का एक आधिकारिक प्रवक्ता नियुक्त करने तथा धार्मिक मामलों के लिए अलग समिति गठित करने

का निर्णय भी लिया गया. बैठक में गठित धार्मिक समिति की अध्यक्षता गोविंद देवगिरी करेंगे. समिति में वासुदेवानंद सरस्वती, विश्वप्रसन्नतीर्थ, दिनेन्द्र दास, कमलनयनदास, राजकुमारदास, रामानंददास और मिथिलेश नंदनी शरण को सदस्य बनाया गया है. ट्रस्ट ने मंदिर के धार्मिक कार्यों और परंपराओं से जुड़े विषयों पर समिति की भूमिका तय करने का भी निर्णय लिया. बैठक के दौरान बैंकिंग व्यवस्था

और वित्तीय कार्यप्रणाली की समीक्षा पर भी चर्चा हुई. इस संबंध में वित्तीय समिति को समीक्षा कर आवश्यक निर्णय लेने की जिम्मेदारी सौंपी गई. साथ ही मंदिर संचालन को और व्यवस्थित बनाने तथा अर्चकों के प्रशिक्षण के लिए प्रशिक्षण केंद्र स्थापित करने का भी निर्णय लिया गया. फिलहाल कृष्ण मोहन कार्यावाहक महासचिव के रूप में अपनी जिम्मेदारी निभाते रहेंगे.

विपक्ष के ब्लैक प्रोटेस्ट से बैकफुट पर सरकार

► राहुल गांधी ने मोदी पर जमकर साधा निशाना

► मोदी को इतिहास का सबसे युवा विरोधी पीएम बताया

प्रवेश कुमार मिश्र

नई दिल्ली, 22 जुलाई. मौजूदा मानसून सत्र सिर्फ विधायी कामकाज की औपचारिकताओं का गवाह नहीं बन रहा, बल्कि यह सत्ता की जवाबदेही और विपक्ष के आक्रामक तत्वों के बीच एक ऐतिहासिक टकराव का अखाड़ा बन चुका है. संसद की दहलीज से लेकर सड़क तक भारतीय लोकतंत्र आज एक बार फिर अपनी पूरी जीवंतता और जटिलता में दिखाई दिया.

मानसून सत्र के दौरान आज विपक्षी सांसदों का संसद के भीतर और बाहर काले कपड़े पहनकर प्रदर्शन करना महज एक सांकेतिक विरोध नहीं है, बल्कि यह हाल के दिनों में उपजे गहरे राजनीतिक अस्तोष का प्रकटीकरण है. पिछले दिनों कांग्रेस नेता राहुल गांधी द्वारा प्रधानमंत्री आवास पर धरना, उनकी सॉफ़ गिरफ्तारी और फिर रिहाई से विपक्ष के हौसलों को जिस तरह धार दी थी, आज का यह देशव्यापी काला प्रदर्शन उसी

का अगली कड़ी के रूप में देखा जा सकता है. काले कपड़ों में एकजुट हुआ विपक्ष यह संदेश देने में सफल रहा है कि वह युवाओं के अधिकारों को लड़ाई को उठे बस्ते में नहीं जाने देगा. विपक्ष इस समय बेहद आक्रामक मुद्रा में है और वह सरकार को किसी भी मोर्चे पर वाकओवर देने के मूड में नहीं है. इतना ही नहीं इस आंदोलन की धारा को राहुल गांधी के तीखे और बेहद संवेदनशील बयान ने और तेज कर दिया, जिसमें उन्होंने सीधे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर हमला बोलते हुए उन्हें भारत के इतिहास का सबसे युवा विरोधी प्रधानमंत्री करार दिया.

राहुल गांधी ने विशेष संवाददाता सम्मेलन में केवल राजनीतिक बयानबाजी नहीं की, बल्कि कुछ बेहद चौंकाने वाले तथ्य देश के सामने रखे. उन्होंने बताया कि पिछले 10 वर्षों में देश में 152 पेपर लीक हो चुके हैं, जिससे 7.5 करोड़ से अधिक छात्रों का भविष्य प्रभावित हुआ है, लेकिन आज तक किसी भी बड़े दोषी को सजा नहीं मिली. राहुल गांधी ने विभिन्न तथ्यों को रखते हुए स्पष्ट किया कि परीक्षाओं की शुचिता का तार-तार होना देश के युवाओं के साथ सबसे बड़ा विश्वासघात है इसलिए विपक्ष तब तक पीछे नहीं हटेगा.